*75वें वर्ष में भारत**

माइकल देबब्रत पात्र

डॉ. हृदयानंद पांडा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भुवनेश्वर, ओडिशा सरकार से आरबीआई के विशिष्ट अतिथि, शिक्षाविद, बैंक, वित्तीय संस्थान, उद्योग संघ, मीडिया, विद्वान और छात्र, भारतीय रिज़र्व बैंक के मेरे सहयोगी, देवियों और सज्जनों !

हमारी आजादी के 75वें वर्ष के उत्सव के हिस्से के रूप में इस संबोधन के लिए आमंत्रित किए जाने पर मैं स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं, डॉ. पांडा को मुझे आमंत्रित करने और उससे भी अधिक अभिनव पहल और शानदार आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उनकी टीम को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिसने इस कार्यक्रम को संभव किया है। इस उल्लेखनीय क्षण में, ऊर्जा, प्रेरणा, नए विचारों और प्रतिज्ञाओं का अमृत हमें एक उज्ज्वल और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे सपनों की पूर्ति से शोभित होगा। कई मायनों में, भुबनेश्वर इस महोत्सव का प्रतीक है - एक समृद्ध और गौरवशाली विरासत; एक सजग वर्तमान; और भविष्य का एक स्मार्ट शहर - हर मामले में, त्रिभुवन।

मेरी बात, पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत की यात्रा को बहुरूपदर्शक बनाने का प्रयास करेगी लेकिन हमारा ध्यान अगले 10-50 वर्षों में भारत के भविष्य पर होगा।

कहा जाता है कि उस विचार से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है जिसका समय आ गया हो।[1] मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का समय आ गया है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस में गाया जाने वाला प्रसिद्ध गीत है[2]- आप कह सकते हैं कि मैं एक सपने देखने वाला हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी बात के बाद, मैं अकेला नहीं रहूंगा। तुम भी मेरे साथ सपने देखोगे, और दुनिया एक जैसी हो जाएगी। इसलिए, मैं आपको सपनों की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं क्योंकि भारत अपनी नियति का साक्षात्कार के लिए तैयार है।

उड़ान के लिए तैयार भारत

ऐसा कहा जाता है कि यदि ब्रह्मांड के इतिहास की तुलना 100 किमी की यात्रा से की जाए, तो 71वें किमी या उससे थोड़ी दूर आगे तक जीवन का सामना नहीं होगा, बल्कि मानव अस्तित्व 1-2 मीटर की अंतिम अवधि में होगा। इस विनम्र नजरिये से देखा जाए तो स्वतंत्र भारत की 75 साल की यात्रा काफी आश्चर्यजनक रही है। 2006 और कोविड-19 महामारी के बीच, भारत में 300 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, दुनिया में कहीं भी गरीबी में कमी की यह उच्चतम दर है। भारतीय अर्थव्यवस्था विभिन्न कृषि वस्तुओं के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। 2021 में, भारत दुनिया के नंबर 1 चावल निर्यातक के रूप में उभरा है जो दुनिया के नंबर 2 और 3 के संयुक्त निर्यात से अधिक है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का सबसे व्यापक आधार विनिर्माण है, जिसमें यह, ट्रैक्टर और दोपहिया वाहन के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक होने के साथ-साथ, स्मार्टफोन, कार और अंतरिक्ष यान के शीर्ष 10 निर्यातकों में शामिल है। शिपिंग कर्मियों और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सहित कई सेवाओं में, भारत विश्व में अग्रणी है। आईटी के मामले में भारत को दुनिया का बैक ऑफिस कहा जाने लगा है।

किसी देश की आर्थिक प्रगति का एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है, जो एक तिमाही या एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। यदि कोई पिछले 75 वर्षों में पीछे मुड़कर देखे, तो सांख्यिकीय परीक्षण (बाई-पेरोन संरचनात्मक ब्रेक टेस्ट) से पता चलता है कि भारत का संवृद्धि पथ तीन चरणों से गुजरा है। 1970 के दशक तक, भारत की औसत जीडीपी संवृद्धि दर 3.6 प्रतिशत थी - तथाकथित हिंदू संवृद्धि दर - जो उस अवधि में अपनाई गई अंत:अवलोकी नीतियों से जुड़ी हुई है। 1980-2002 के दौरान उदारीकरण, खुलेपन और एक बाह्य उन्मुखीकरण के कारण संवृद्धि दर 5.5 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसके बाद, महामारी आने तक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि औसतन लगभग 7 प्रतिशत हो गई। 2020-21 में महामारी के

---

* 13 अगस्त 2022 को भारतीय रिज़र्व बैंक, भुबनेश्वर द्वारा आयोजित **आज़ादी का अमृत महोत्सव** के निमित्त एक कार्यक्रम में डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण। राजीव जैन, अत्रि मुखर्जी, वी. धन्या, धीरेंद्र गजभिए, आशीष थॉमस जॉर्ज, हरेंद्र बेहरा, सोना थंगजानसन और कुणाल प्रियदर्शी के मूल्यवान इनपुट और टिप्पणियां; और विनीत कुमार श्रीवास्तव और समीर रंजन बेहरा की संपादकीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया जाता है।

1 विक्टर ह्यूगो, हिस्टोर डी'न क्राइम, 1877

2 इमैजिन, जॉन लेनॉन।

कारण जीडीपी में 6.6 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2021-22 में, यह 8.7 प्रतिशत तक बहाल हो गया और जीडीपी को अपने पूर्व-महामारी स्तर से 1.5 प्रतिशत ऊपर ले गया। चालू वित्त वर्ष, यानी 2022-23 के लिए, आरबीआई ने सकल घरेलू उत्पाद में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में रखता है।

भारत की संवृद्धि के कारक क्या हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था "हम" लोगों के निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) द्वारा संचालित है, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, किराए, बीमा, पेंशन अंशदानों और इस तरह अन्य व्यय - जो दैनिक आजीविका से संबद्ध हैं - पर परिवारों के खर्च शामिल हैं। निजी खपत सकल घरेलू उत्पाद का 55 प्रतिशत है, हालांकि यह हिस्सा 1960 के दशक के 75 प्रतिशत से अधिक से नीचे आ गया है। निर्यात-आधारित और निवेश-आधारित संवृद्धि के चरण रहे हैं, जो कायम नहीं रह सके, लेकिन उन्होंने संवृद्धि पथ में महत्वपूर्ण मोड़ दिए। विशेष रूप से, निवेश को - जो वस्तुओं का उत्पादन है और जिसके बदले अन्य वस्तुओं का उत्पादन होता है - भारत की काया पलट करने वाला माना जा रहा है क्योंकि अधिकांश विकासशील देशों में पूंजी की कमी है। निवेश दर (कुल निवेश बटा जीडीपी) को व्यापक रूप से भारत में संवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है।

भारत में एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि हमारी संवृद्धि घरेलू-वित्तपोषित है - निवेश मुख्य रूप से घरेलू बचत द्वारा वित्तपोषित है, विदेशी बचत केवल एक पूरक भूमिका निभाती है। एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 2007-08 से बचत दर धीमी होने लगी है। आखिरकार, इसने निवेश दर को नीचे खींच लिया, जिसने 2012-13 से मंदी का प्रदर्शन किया है। उच्च संवृद्धि हासिल करने के लिए इस प्रवृत्ति को उलटना महत्वपूर्ण है।

देश के भुगतान संतुलन (बीओपी) में चालू खाता घाटा (सीएडी) यह निर्धारित करता है कि देश में कितनी बाह्य बचत या निवल पूंजी अंतर्वाह को अवशोषित अथवा संवृद्धि के लिए उपयोग किया जा सकता है। निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं जबकि आयात के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। भारत जैसा देश उन वस्तुओं के आयात के लिए दुनिया के बाकी हिस्सों पर निर्भर है जिनका हम उत्पादन नहीं करते हैं जैसे कि कच्चा तेल और ऐसी मशीनरी, उपकरण और तकनीक जैसी वस्तुएं जिनमें या तो अन्य देशों के पास तुलनात्मक लाभ है या उनके पास उपलब्धता अधिक है। भारत के लिए, आयात आम तौर पर निर्यात से अधिक होता है, इसलिए आयात भुगतान की पूर्ति हेतु विदेशी मुद्रा से पर्याप्त कमाई नहीं होती है। इस अंतराल को विदेश से उधार लेकर भरा जाता है, हालांकि, इसको मूलधन और ब्याज का भुगतान कर चुकाया जाता है। यदि कर्ज़ की चुकौती हमारी आय से अधिक हो जाती है, तो हमें या तो आयात कम करना होगा और अपनी संवृद्धि संभावनाओं को संकुचित करना होगा या कर्ज़ अदायगी में चूक करनी होगी और अंतरराष्ट्रीय अलगाव को झेलना पड़ेगा। हमारा अनुभव रहा है कि भारत बाहरी क्षेत्र के संकट में पड़े बिना 2.5-3.0 प्रतिशत का चालू खाता घाटा बनाए रख सकता है। वास्तव में, इस तथ्य की याद दिलाते हुए, तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि और स्वर्ण-आयात आधिक्य ने चालू खाता घाटा को प्लिमसल लाइन से ऊपर और 2011-13 के दौरान ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँचा दिया। जब यूएस फेडरल रिज़र्व ने 2013 की गर्मियों में सहज मौद्रिक नीति के अंत पर विचार किया, तो भारत को टेपर घटनाक्रम का सामना करना पड़ा और उसे कमज़ोर पांच का नाम दिया गया।[3]

अंतर-देशीय परिप्रेक्ष्य

थोड़ा पीछे जाकर, अंतर-देशीय परिवेश में भारत की प्रगति का निरीक्षण करना उपयोगी होगा। मैं 1960 के दशक की शुरुआत से दुनिया की शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं के उत्थान और पतन की ओर मुड़ना चाहता हूं जब एशिया के विकासशील देशों ने दो शताब्दियों के पश्चिमी वर्चस्व के बाद नई शुरुआत के लिए रणनीतियां बनानी शुरू कीं। जापान का युग ध्यान देने योग्य है जो 1960 के दशक में शुरू हुआ और 1970 और 1980 के दशक तक चला। चीन का युग 1990 के दशक के आरंभ में शुरू हुआ, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति में ले गया। 2015 से भारत का समय आता दिख रहा है। आज भारत बाजार विनिमय दरों के मामले में दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

[3] कमज़ोर पांच- ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की थे।

वर्ष 2022 के लिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2022 में 3.2 प्रतिशत की वैश्विक संवृद्धि का अनुमान लगाया है, जो 2021 के 6.1 प्रतिशत से कम है। भारत को 2022 में 7.4 प्रतिशत की संवृद्धि का अनुमान है। महामारी और यूरोप में युद्ध के बावजूद, भारत वैश्विक संवृद्धि में लगभग 14 प्रतिशत का योगदान करने जा रहा है। वास्तव में, भारत चीन के बाद 2022 में वैश्विक संवृद्धि का **दूसरा** सबसे महत्वपूर्ण चालक हो सकता है।

जीडीपी द्वारा मापे गए आर्थिक प्रदर्शन की परस्पर-तुलना के लिए बाजार विनिमय दरों के उपयोग पर सवाल उठाए गए हैं। आखिरकार, विनिमय दरें अस्थिरता और विचलन-वृत्ति से प्रभावित होती हैं जो उन्हें वास्तविकता से अलग कर देती हैं। क्रय शक्ति समता एक वैकल्पिक उपाय है। यह माल (वस्तु) और सेवाओं की एक औसत बास्केट की कीमत है जिसकी प्रत्येक देश में आजीविका के लिए एक परिवार को आवश्यकता होती है। एक अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला उदाहरण मैकडॉनल्ड का बर्गर है, जिसके बारे में माना जाता है कि हर देश में हर आउटलेट में एक ही गेहूं, आलू और अन्य सामग्री होती है। आपको यह दिखाने के लिए कि यह कैसे काम करता है, एक बड़े मैक के लिए यूएस में भुगतान किए गए पैसे से भारत में 2.5 मैक खरीद सकते हैं।

तो, यह हमें विनिमय दर और जीडीपी के बारे में क्या बताता है? वर्तमान में भारत, क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका वैश्विक जीडीपी में 7 प्रतिशत हिस्सा है [चीन (18 प्रतिशत) और अमेरिका (16 प्रतिशत) के बाद]। बाजार विनिमय दरों में भारत की जीडीपी 2027 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उस वर्ष तक, क्रय शक्ति समता के संदर्भ में भारत की जीडीपी 16 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (2021 में यूएस $ 10 ट्रिलियन से अधिक) से अधिक हो जाएगी। ओईसीडी की 2021 की गणना बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2048 तक अमेरिका से आगे निकल जाएगी। यह भारत को चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगा।

पीपीपी के संदर्भ में, विनिमय दर किसी राष्ट्र की समृद्धि और उसकी उत्पादकता में वृद्धि के साथ बढ़ती है। इंडोनेशियाई रुपिया दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा बनने के लिए तैयार है, जबकि भारतीय रुपया दूसरी सबसे मजबूत मुद्रा के रूप में उभर रहा है।

अवसर

आज भारत जहां है, उसकी विहंगम छवि के साथ, मैं उन चार इंजनों की चर्चा करूँगा जो भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने हेतु उदीयमान अर्थव्यवस्था रूपी कक्षा से उन्नयन के लिए पलायन वेग और शक्ति प्रदान कर सकते हैं।

(i) जनसांख्यिकीय स्थिति

मैं, बहु-उद्धृत जनसांख्यिकीय लाभ की अंतर्निहित वास्तविकताओं के साथ शुरूआत करूँगा। 2021 में पहली बार दुनिया की जनसंख्या वृद्धि 1 प्रतिशत से नीचे गिर गई। यह इस सदी के बाकी समय में धीमी हो जाएगी। 1.38 बिलियन की भारत की आबादी 28.4 वर्ष की दुनिया की सबसे युवा आबादी है। 2023 तक (यानी अगले साल), भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश (1.43 बिलियन) होगा।[4]

2045 तक वृद्धावस्था के कारण भारत के युवा होने के लाभ बंद हो जाएँगे, जैसा कि 2004 में जापान और 2002 में इटली में हुआ था। यह जनसंख्या की बदलती संरचना से स्पष्ट है। एक प्रमुख संकेतक कुल प्रजनन दर है - एक महिला के अपने जीवनकाल में पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या। भारत के नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21) के निष्कर्षों के अनुसार, 2.0 की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) (2015-16 में 2.2 से नीचे और 2005-06 में 2.7) पहली बार प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के अनुसार, 2.1 से कम कुल प्रजनन दर[5] वाली पीढ़ी अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप उस देश की जनसंख्या में एकमुश्त कमी आती है। दूसरी ओर, भारतीयों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है और 2099 तक लगभग 70 वर्षों के वर्तमान स्तर से बढ़कर लगभग 82 वर्ष होने की संभावना है।

भारत की कामकाजी-आयु[6] जनसंख्या (डब्ल्यूएपी) के अनुपात की कुल जनसंख्या के साथ अन्य देशों, अर्थात, चीन, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की तुलना से पता चलता है कि भारत लाभप्रद स्थिति में है। इन देशों की कामकाजी

4 विश्व जनसंख्या संभावनाएँ 2022; संयुक्त राष्ट्र, जुलाई 2022।

5 प्रति महिला बच्चों की संख्या।

6 15 - 64 वर्ष के रूप में परिभाषित।

आयु वाली आबादी पहले से ही घटनी शुरू हो गई है, जबकि भारत का डब्ल्यूएपी अनुपात 2045 तक बढ़ जाएगा, यहां तक कि 2030 तक चीन से भी अधिक हो जाएगा। इस जनसांख्यिकीय लाभ का अधिकतम उपयोग करना भारत के लिए अवसर के साथ-साथ एक चुनौती भी है।

(ii) विनिर्माण

उड़ान के लिए एक और इंजन विनिर्माण है। भारत के विकास के अनुभव को व्यापक रूप से उल्लेखनीय माना गया है क्योंकि यह प्राथमिक गतिविधियों से द्वितीयक और फिर तृतीयक गतिविधियों की ओर बढ़ने वाले देश के सामान्य पथ से अलग हो गया है।[7] भारत ने द्वितीयक चरण के उपर छलांग लगाकर प्राथमिक गतिविधियों से तृतीयक क्षेत्र की ओर आ गया। आज सेवा क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में दो-तिहाई हिस्सा है।

पीछे देखने पर, भारतीय अनुभव का यह चमत्कार नहीं हो सकता था जैसा अभिहित किया जाता है - भारत, कृषि से पलायन करने वाले अपने कम-कुशल श्रम बल को बड़े पैमाने पर लाभकारी रोजगार में अवशोषित करने में विफल रहा। इस श्रम अवशोषण क्षमता के अलावा, विनिर्माण क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ पश्चगामी और अग्रगामी संबंध हैं। भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण में सशक्त वृद्धि जरूरी है। इसलिए यह आवश्यक है कि पारंपरिक विवेक को बदलकर और दुनिया के अन्य अग्रणी विनिर्माताओं के साथ रफ्तार बना ली जाए।

विश्व बैंक के अनुसार, भारत का विनिर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में (स्थिर 2015 के अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में) विश्व औसत के साथ-साथ अधिकांश साथी-देशों से बहुत नीचे है। भारतीय विनिर्माण की वृद्धि काफी अस्थिर रही है, जो 17.8 प्रतिशत (2006-07) के शिखर और -3.2 प्रतिशत (1979-80) के निचले स्तर के बीच रही है। 1990 के दशक से विनिर्माण में औसत वृद्धि 7.0-7.5 फीसदी रही है। यदि अगले दशक में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की जाती है, तो विनिर्माण 2030-31 तक समग्र वर्धित सकल मूल्य (जीवीए) के 20.4 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। अगर विनिर्माण को - 'मेक इन इंडिया' अभियान द्वारा निर्धारित लक्ष्य -10 फीसदी की दर से बढ़ना है तो इसका हिस्सा 2030-31 में 25 फीसदी तक पहुंच जाएगा। रोजगार और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव के साथ भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर बन जाएगा।

इसे हासिल करने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले, विनिर्माण क्षेत्र को चौथी औद्योगिक क्रांति (ऑटोमेशन; डेटा एक्सचेंज; साइबर-फिजिकल सिस्टम; इंटरनेट ऑफ थिंग्स; क्लाउड कंप्यूटिंग; कॉग्निटिव कंप्यूटिंग; स्मार्ट फैक्ट्री; और उन्नत रोबोटिक्स)[8] के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा, भारत को मानव पूंजी में निवेश बढ़ाकर एक कुशल श्रम शक्ति का विकास करना चाहिए। तीसरा, विनिर्माण को वैश्विक बाजारों में उपस्थिति की तलाश हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए। वैश्विक विनिर्माण केंद्र (हब) बनने के लिए भारत को जीडीपी के कम से कम 25 फीसदी तक विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी।

(iii) निर्यात

निर्यात राष्ट्रीय सीमाओं से परे बाजारों और उत्पादन क्षमताओं के विस्तार के लिए एक अवसर प्रदान करता है। वर्तमान में, भारत के माल और सेवाओं का निर्यात 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है, जो दुनिया के कुल निर्यात का 2.7 प्रतिशत है। भारत सरकार ने 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे भारत की हिस्सेदारी वैश्विक कुल का 5 प्रतिशत हो जाएगी और भारत एक निर्यात महाशक्ति बन जाएगा। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए कई पहल की जा रही हैं:

- एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल 'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' की अवधारणा को एकीकृत करती है;
- निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना निर्यातित माल पर - निर्यात मूल्य के 0.5 - 4.3 प्रतिशत के रेंज में - प्रतिदेय करों के

[7] प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कृषि और संबद्ध गतिविधियों, खनन और उत्खनन से संबंधित है; द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि विनिर्माण, बिजली उत्पादन और निर्माण से संबंधित है; तृतीयक गतिविधि सेवाओं से संबंधित है।

[8] पहली औद्योगिक क्रांति 1760-1900 के दौरान हुई, जो कोयला, भाप के इंजन और ट्रेनों द्वारा संचालित थी। दूसरी क्रांति 1870-1940 के बीच तेल, बिजली, अंतर्दहन इंजन और कार द्वारा संचालित हुई। तीसरी क्रांति 1930-2000 के बीच हुई और यह परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कंप्यूटर, रोबोट और विमानों पर आधारित थी।

रूप में प्रोत्साहन प्रदान करती है जो लगभग 8555 उत्पाद लाइनों को कवर करता है।

- उभरते सितारे योजना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को उनकी निर्यात क्षमता को साकार करने में सहायता करती है;
- राज्य और केंद्रीय करों और लेवी में छूट (आरओएससीटीएल) योजना का उद्देश्य परिधान/गारमेंट्स के निर्यात को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस योजना के तहत, परिधान, वस्त्र और मेड-अप के निर्यातकों को एम्बेडेड टैक्स और लेवी वापस कर दिए जाते हैं, जिस पर वर्तमान में किसी अन्य तंत्र के तहत छूट नहीं दी जा रही है;
- आईटी और डिजिटल सेवाओं, उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों, उच्च मूल्य वाले पर्यटन, वित्तीय सेवाओं, खुदरा और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में निर्यात क्षमता का दोहन किया जाना है।

विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कम से कम 5 प्रतिशत तक बढ़ाना पहुंच के भीतर है।

(iv) अंतरराष्ट्रीयकरण

भारतीय दुनिया में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीयकृत लोगों में से हैं। भारतीय डायस्पोरा दुनिया में सबसे बड़ा है और भारत धन-प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता है। भारतीय रुपया देशस्थ की तुलना में तीन गुना अधिक विदेशस्थ व्यापार करता है। फिर भी हम अभी भी अंतरराष्ट्रीयकरण की बात करते हैं जैसे कि यह एक अंतिम सीमा है। अर्थशास्त्री नियाल फर्ग्यूसन लिखते हैं कि मानव इतिहास में 70 साम्राज्य हुए हैं। 69वां और 70वां साम्राज्य क्रमशः चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ हैं। 68वें साम्राज्य में एक साम्राज्य के सभी गुण हैं, जिसमें अपनी सीमाओं से परे युद्ध छेड़ना भी शामिल है। फिर भी यह मौलिक तरीके से भिन्न है - यह विदेशी भूमि को अपने में शामिल नहीं करता है। फर्ग्यूसन इसे उदासीन साम्राज्य कहते हैं - यह यूएसए है। एक सादृश्य बनाते हुए, भारत को एक उदासीन अंतरराष्ट्रीयकारी के रूप में माना जा सकता है। यदि भार.रु. (आईएनआर) का कुल कारोबार वैश्विक विदेशी मुद्रा कुल कारोबार (4 प्रतिशत) में गैर-अमेरिकी गैर-यूरो मुद्राओं के हिस्से के बराबर हो जाता है, तो आईएनआर एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में सामने आ चुका होगा, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को दर्शाएगा।

चुनौतियाँ

आइए अब मैं उन चुनौतियों का समाधान करता हूं जो उड़ान भरते समय रनवे पर हमारे सामने आती हैं। मेरे विचार से फोकस चार प्रमुख चुनौतियों पर होना चाहिए। पहली, **महामारी के कारण उत्पादन और आजीविका का नुकसान है।** आपूर्ति में व्यवधान, स्वास्थ्य संकट, एक ऐतिहासिक सामूहिक प्रवासन और शत्रुतापूर्ण वैश्विक वातावरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाला। मांग में कमी और आपूर्ति में व्यवधान का संयोजन जो महामारी में शुरु हुआ था, से गंभीर प्रभाव पड़ा। जैसा कि पहले कहा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में 6.6 प्रतिशत तक सिकुड़ गई। उस वर्ष की पहली तिमाही में जब महामारी की पहली लहर भड़की थी, जीडीपी 24 प्रतिशत तक सिकुड़ गई थी, जो दुनिया में सबसे तीव्र थी। यदि एक ट्रेंड लाइन को भारत के सकल घरेलू उत्पाद के स्तर पर फिट किया जाता है और 2013-20 में प्रचलित 6.6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर 2021-22 तक बढ़ाया जाता है, तो वास्तविक जीडीपी के साथ इस प्रवृत्ति जीडीपी की तुलना में 2020-21 और 2021-22 महामारी के कारण हुए नुकसान का एक स्थूल आकलन मिलेगा।

इस उत्पादन हानि की भारपाई में कई साल लग सकते हैं – मैं, इसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मानता हूँ।

दूसरी चुनौती भारत का **अवसंरचना अंतराल** है। अवसंरचना (बुनियादी ढांचा) में भारत का प्रति व्यक्ति निवेश दुनिया में सबसे कम है (स्थिर 2015 डॉलर में 88.6 अमेरिकी डॉलर)। भारत द्वारा अवसंरचना निवेश वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.6 प्रतिशत है। यदि भारत सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के बराबर अवसंरचना में निवेश करता है, तो यह 2030 तक यूएस $7.5 ट्रिलियन का जीडीपी स्तर हासिल कर लेगा- जैसा कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब[9] द्वारा अनुमान लगाया गया है; और अवसंरचना अंतराल समाप्त हो जाएगा। यह 2027 तक 5 ट्रिलियन

[9] जी20 द्वारा समर्थित एक गैर-लाभकारी संगठन।

अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के हमारे लक्ष्य के अनुरूप भी है।

अवसंरचना निर्माण (इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव) के लिए मुख्य आवश्यकताएं पारदर्शी और तेज विनियामक प्रक्रियाएं; स्पष्ट, पारदर्शी और कुशल भूमि अधिग्रहण और जलवायु मंजूरी नीतियां; और व्यवहार्य अवसंरचना वित्त हैं जो अवसंरचना परियोजनाओं की संकल्पनात्मक अवधि को भी ध्यान में रखे। विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण भारत की उड़ान के लिए अगली बड़ी चुनौती है।

तीसरी चुनौती एक **उच्च गुणवत्ता वाली श्रम शक्ति** का विकास करना है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में, गुणवत्ता और मात्रा दोनों के संदर्भ में श्रम का योगदान विकसित और कई उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है। 83 प्रतिशत कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। जैसे-जैसे भारत एक विनिर्माण केंद्र और निर्यातक महाशक्ति के रूप में बदल रहा है, कार्यबल को समय के साथ विस्तार और अधिक कुशल बनना होगा। मात्रा के बजाय सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। भारत की कुल श्रम शक्ति में, रोजगार योग्यता (किसी विशेष नौकरी के लिए उपयुक्त कौशल) 50 प्रतिशत से कम है। इस बाधा को तोड़ने का एक महत्वपूर्ण उत्तोलक, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। विश्व बैंक, (वैश्विक विकास संकेतक) के अनुसार, भारत 2020 में महिला श्रम बल भागीदारी दर के मामले में 187 देशों में 178वें पायदान पर है।

हमें ऐसे कार्यस्थलों का निर्माण करना चाहिए जो कार्यस्थल पर महिलाओं को कलंकित न करें और इसके बजाय उन्हें सम्मान और संतुष्टि के साथ अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए कामकाजी महिलाओं के पक्ष में सामाजिक सोच निर्मित करने; छात्रों और कर्मचारियों की विविधता बनाए रखने के लिए संस्थानों को प्रोत्साहन देने; काम के सुविधाजनक घंटे; कार्यस्थलों पर महिलाओं की सहूलियत के लिए नीतियां और सुविधाएं, सहित जो कामकाजी माता-पिता के लिए अनुकूल कराधान प्रणाली, कार्यस्थलों पर अनिवार्य मातृत्व/पितृत्व अवकाश, घर के करीब काम की उपलब्धता और नौकरियों के अधिक अवसर निर्मित करने, की आवश्यकता है। उच्च गुणवत्ता वाली श्रम शक्ति विकसित करने के लिए महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

चौथी चुनौती **हरिततर और स्वच्छतर** भारत है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में पार्टियों के सम्मेलन 26 (सीओपी26) में, भारत ने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए पंचामृत नामक पांच प्रतिज्ञाएँ लीं। इनमें शामिल हैं (i) 2030 तक 500 गीगावाट (जीडब्ल्यू) गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना; (ii) 2030 तक 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा युक्त ऊर्जा मिश्रण; (iii) अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन कम करना; (iv) 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45 प्रतिशत से कम करना; और (v) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को यथासंभव शून्य के करीब लाकर 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। उपर्युक्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्त-स्तर महत्वपूर्ण है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद[10] ने अनुमान लगाया है कि 2070 तक निवल-शून्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए यूएस $10.1 ट्रिलियन के संचयी निवेश की आवश्यकता है। इसमें से, यूएस $8.4 ट्रिलियन निवेश की आवश्यकता अकेले बिजली क्षेत्र रूपांतरण - नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव - को पूरा करने के लिए है। उद्योग (कोयले में कमी और हाइड्रोजन के उपयोग में वृद्धि) के लिए यूएस $1.5 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी, और जंगम क्षेत्र (मोबिलीटी सेक्टर) को यूएस $198 बिलियन की आवश्यकता होने का अनुमान है।

हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में उम्मीद की किरण है। 2030 तक 500 जीडब्ल्यू तक पहुंचने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा को 14.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ना चाहिए। विकास की वर्तमान औसत दर 18.7 प्रतिशत (2014-15 से 2020-21) पर, हम 2027 तक 500 जीडब्ल्यू लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

अक्षय ऊर्जा उत्पादन और वास्तविक बिजली खपत के समय के बीच अंतर को कम करने के लिए भारत को पर्याप्त ऊर्जा भंडारण सुविधाओं की आवश्यकता होगी। हमें संचार और वितरण में होने वाली क्षति को कम करना होगा। हमें नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रीय संकेन्द्रण को ठीक करना होगा क्योंकि यह स्थान विशिष्ट - ज्यादातर दक्षिणी राज्य - है और समान रूप से वितरित नहीं है। उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने वाली क्रॉस-सब्सिडी से बचते हुए टैरिफ संरचना में वास्तविक लागत प्रतिबिंबित होना चाहिए। साथ ही, हमें डिस्कम्स के पुराने कर्ज की समस्या का समाधान खोजना होगा।

[10] एशिया का अग्रणी गैर-लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान।

निष्कर्ष

यदि भारत अपने अवसरों को भुनाता है और इस वार्ता में मैंने जिन चुनौतियों का उल्लेख किया है, उन पर काबू पा लेता है, तो यह व्यापक रूप से माना जा सकता है कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है। इसलिए, क्रय शक्ति समता अनुमानों पर फिर से विचार करते हुए, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, यह कल्पना करना संभव है कि भारत अगले दशक में 11 प्रतिशत की संवृद्धि दर के साथ आगे बढ़ेगा। यदि यह हासिल हो जाता है, तो भारत 2048 तक नहीं बल्कि 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जैसा कि पहले कहा गया है। यहां तक कि अगर यह इस गति को बनाए नहीं रखता है और 2040-50 के दौरान 4-5 प्रतिशत तक धीमा हो जाता है, तो यह 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

जैसा कि मैंने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा था, आप सोच सकते हैं कि मैं एक सपने देखने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब इतिहास खुद को दोहराता नहीं है तो यह अक्सर अपनी चाल की पुनरावृत्ति करता है। प्रतिष्ठित ब्रिटिश अर्थशास्त्री आंगस मैडिसन जो आर्थिक संवृद्धि और विकास के मापन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं, ने दुनिया के हर महाद्वीप के प्रमुख देशों के आर्थिक प्रदर्शन का लंबे समय तक दस्तावेजीकरण किया है। उनके कार्यों के अनुसार 1 से 1000 ईस्वी के दौरान विश्व जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। अगले 600 वर्षों में, भारत रुक-रुक कर दूसरे स्थान पर आ गया, लेकिन 1700 ईस्वी तक विश्व जीडीपी के 24.4 प्रतिशत हिस्से के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान पुनः प्राप्त कर लिया। तब से, इस हिस्सेदारी की अपूरणीय क्षति हुई है। देवियो और सज्जनो, समय आ गया है कि इस गिरावट को रोका जाए और इसे पलट कर विश्व मंच पर अपना उचित स्थान पुनः हासिल किया जाए।

धन्यवाद !

अनुबंध

चार्ट 1: भारत की जीडीपी संवृद्धि का उद्भव

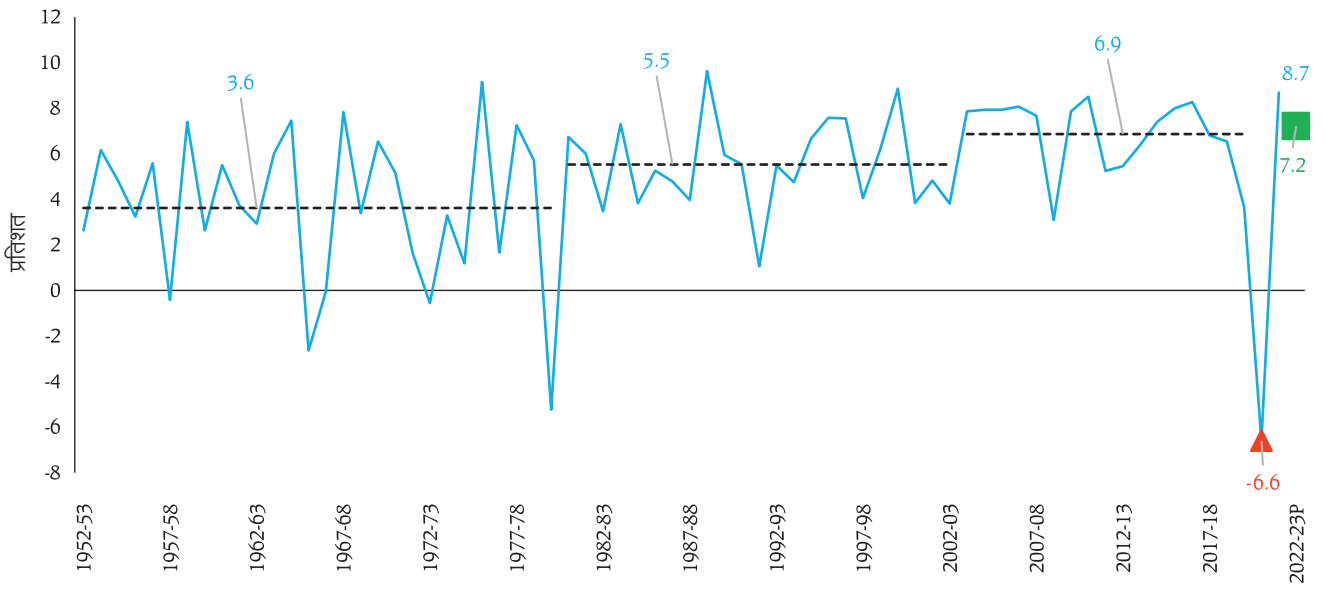

चार्ट 2: सनिवेश उपभोग चालित/निर्यात चालित कालखंड

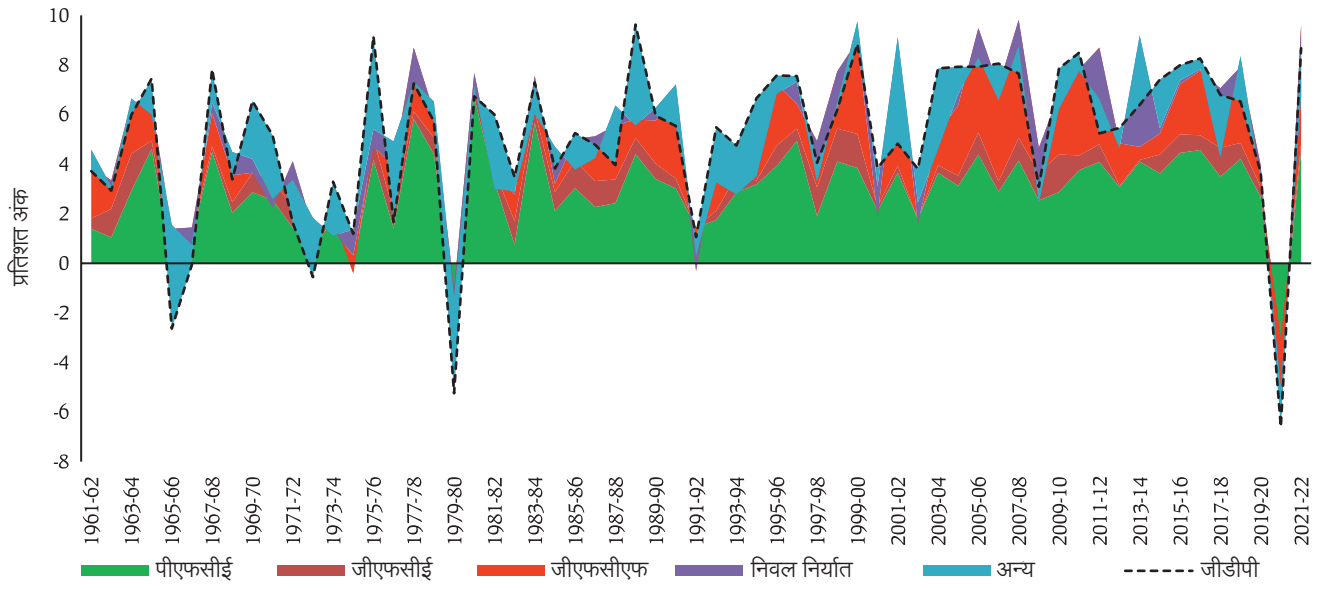

चार्ट 3: बचत-निवेश दर (जीडीपी के प्रतिशत में)

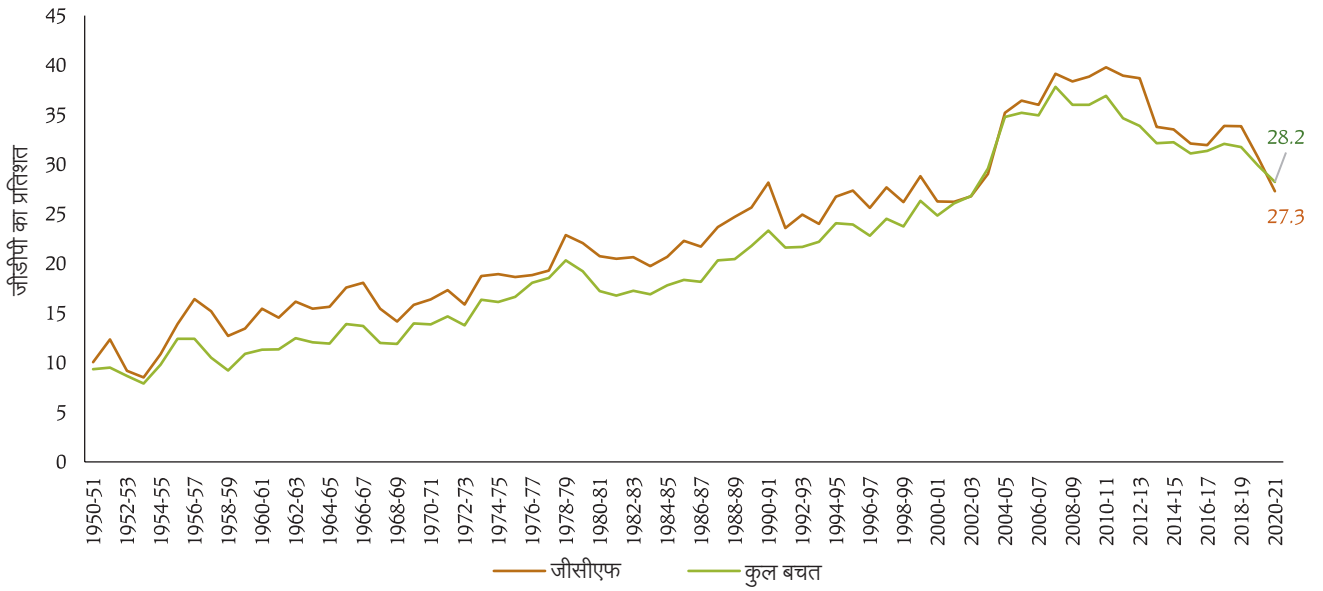

चार्ट 4: चालू खाता घाटा (जीडीपी के प्रतिशत में)

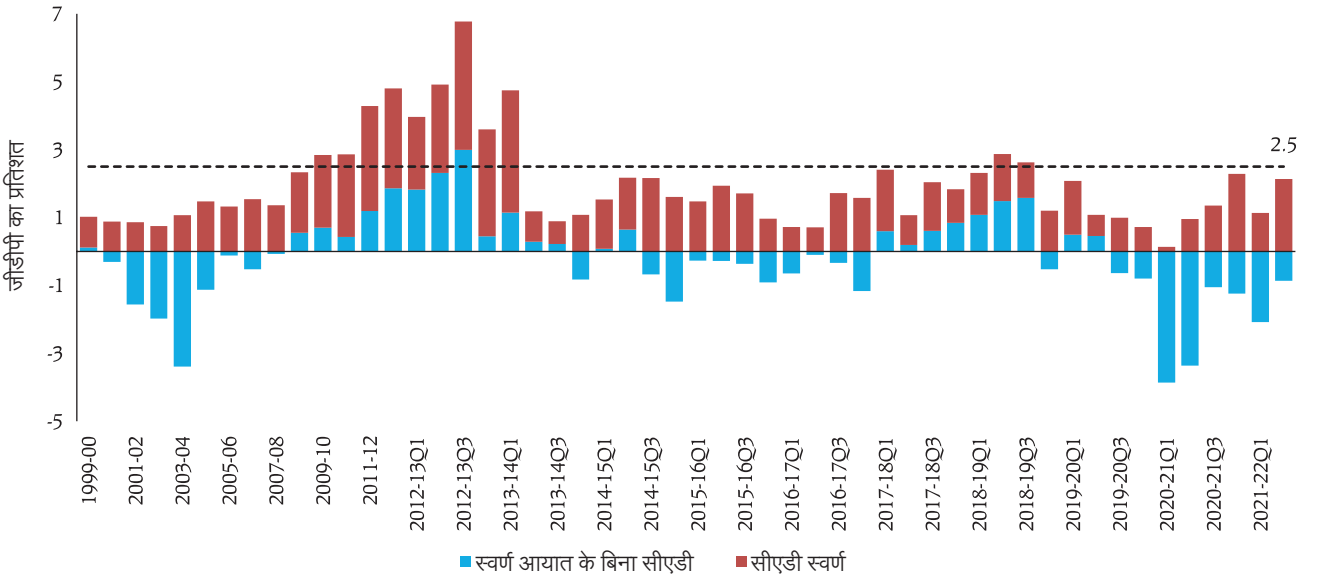

चार्ट 5: विश्व जीडीपी : संवृद्धि में योगदान

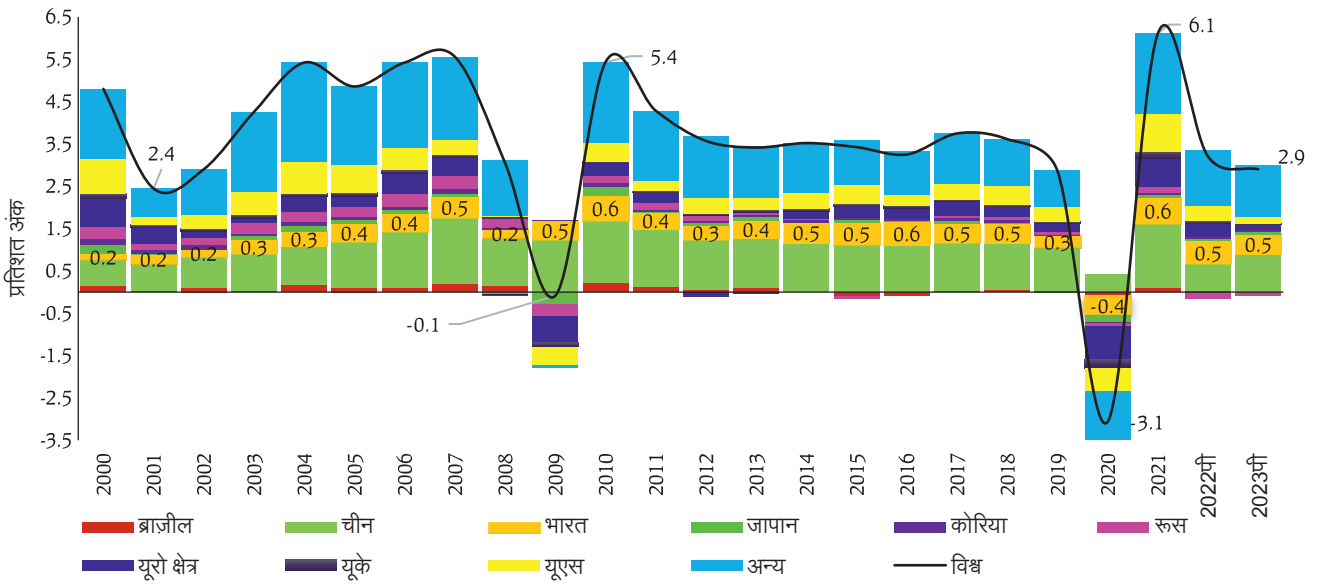

चार्ट 6: 2020 में विश्व जीडीपी में हिस्सेदारी (पीपीपी के रूप में)

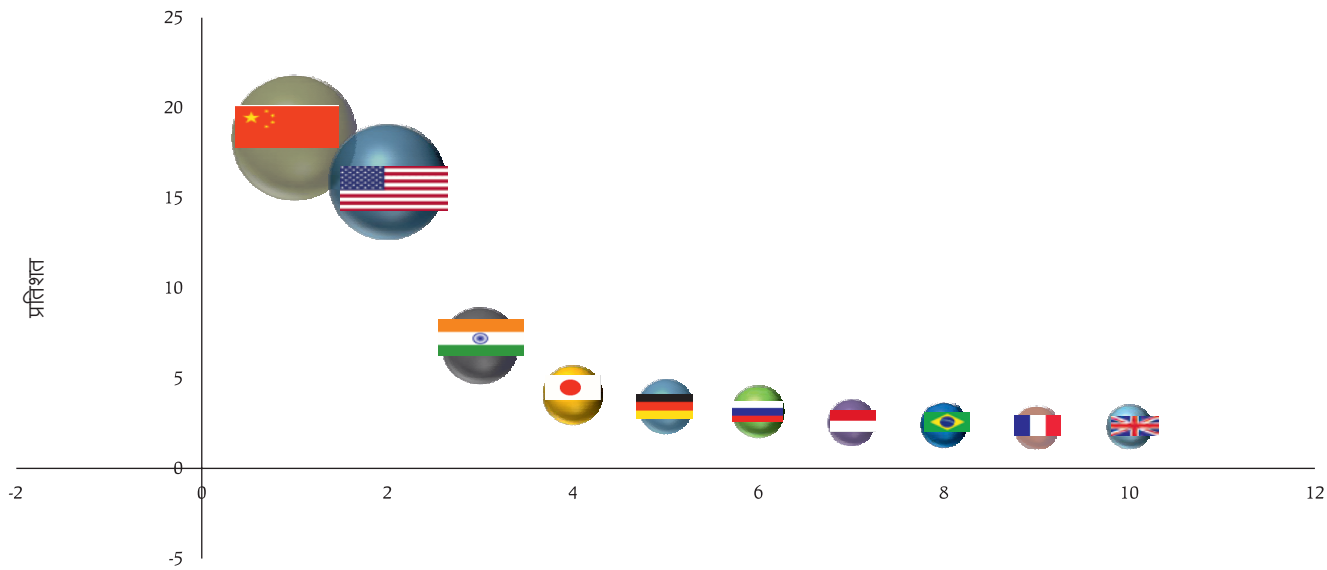

चार्ट 7: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक जीडीपी

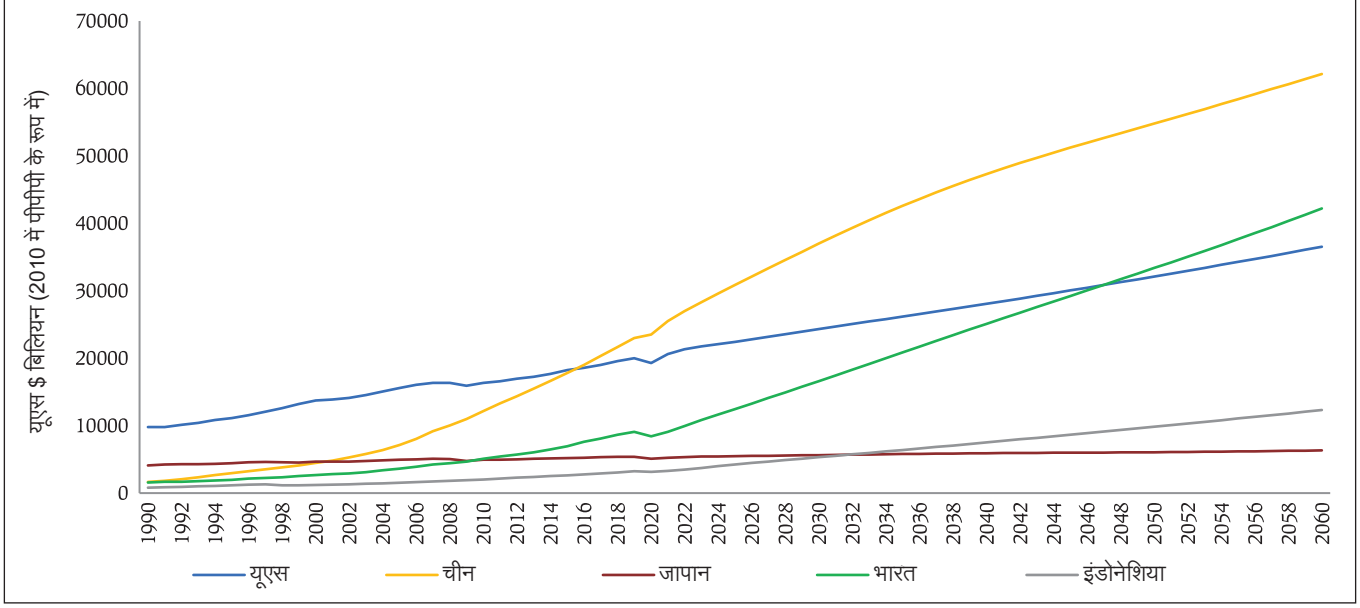

चार्ट 8: पीपीपी विनिमय दर

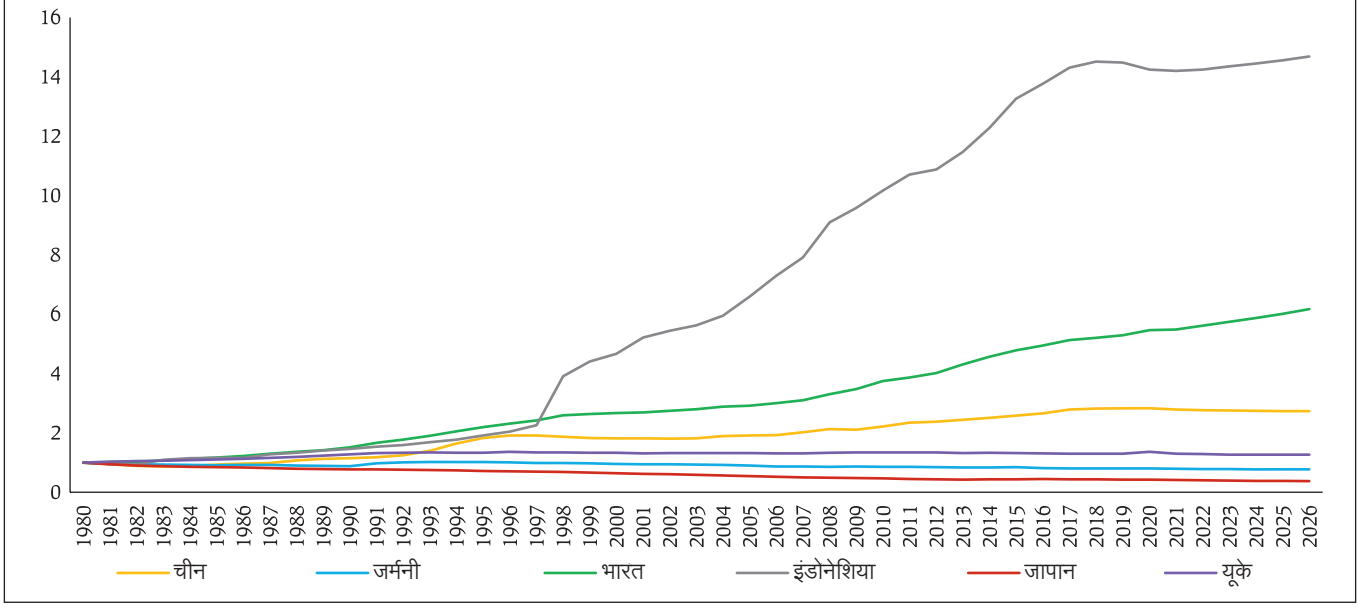

चार्ट 9: जनसांख्यिकीय लाभ

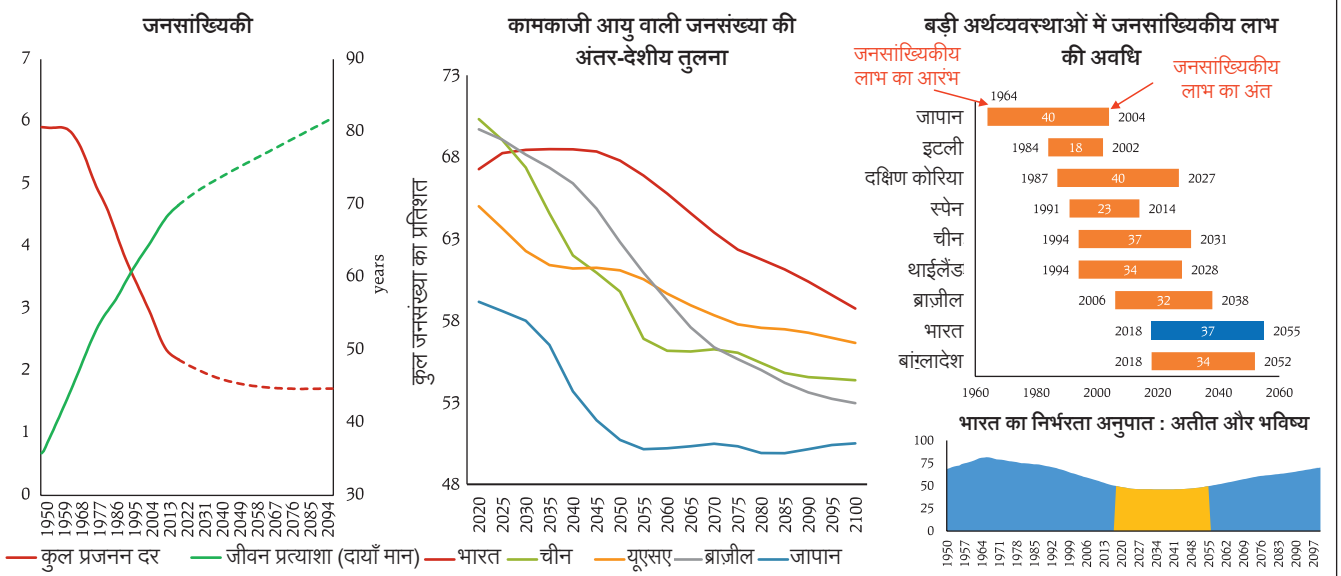

चार्ट 10: विश्व का विनिर्माण केंद्र

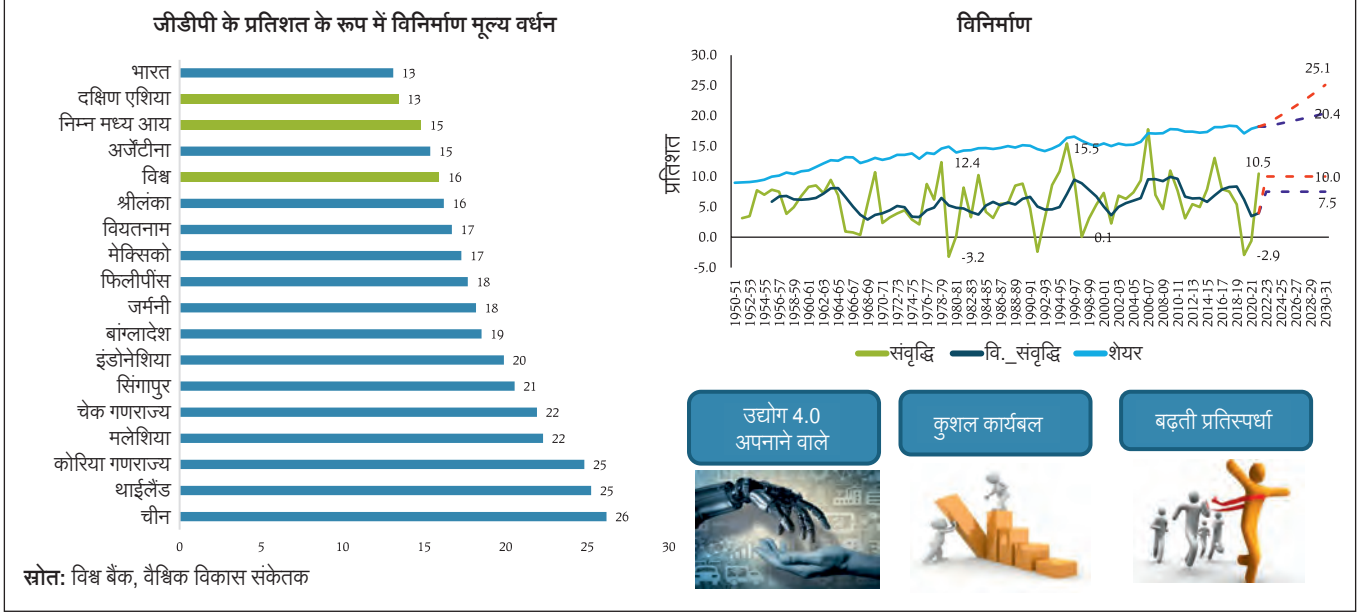

स्रोत: विश्व बैंक, वैश्विक विकास संकेतक

चार्ट 11: निर्यात महाशक्ति

2029-30 तक भारत का निर्यात

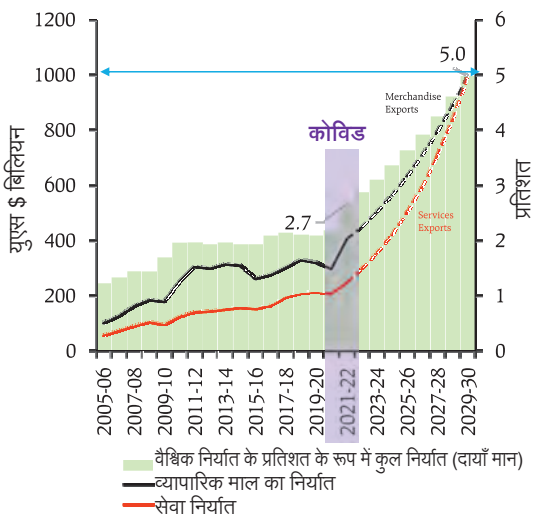

एक जिला एक उत्पाद योजना (ओडीओपी)

- निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ
- आरओडीटीइपी योजना
- उभरते सितारे योजना
- आरओएससीटीएल

वैश्विक आईटी और डिजिटल सेवा केंद्र $ 285 बि.

उच्च मूल्य कृषि परितंत्र $ 145 बि.

उच्च मूल्य पर्यटन $ 50 बि.

नेक्स्ट जेन वित्तीय सेवाएँ $ 335 बि.

ई-अभिशासन $ 65 बि.

आधुनिक खुदरा और ई-व्यापार $ 125 बि.

चार्ट 12: अंतरराष्ट्रीयकरण

वैश्विक प्रसार

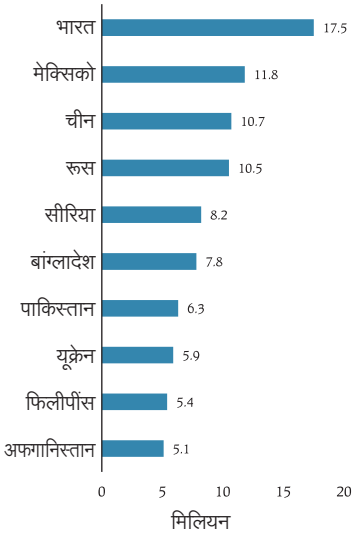

भारतीय रुपया : देशस्थ प्रदेय वायदा में औसत प्रतिदिन कुल कारोबार *बनाम* एनडीएफ

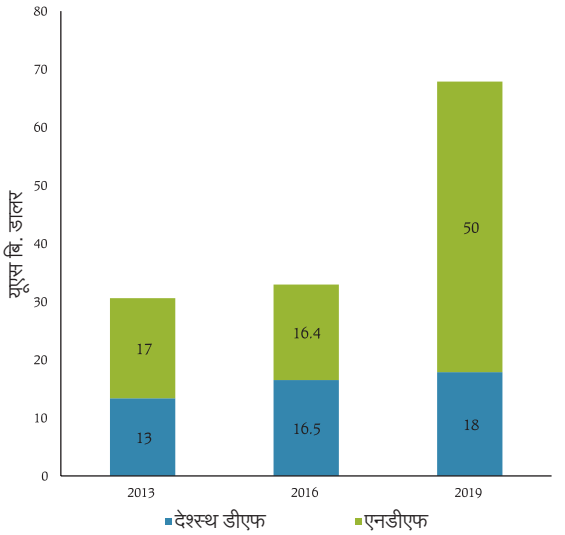

2030 तक भा.रु. एफएक्स कारोबार के लिए सांकेतिक बेंचमार्क

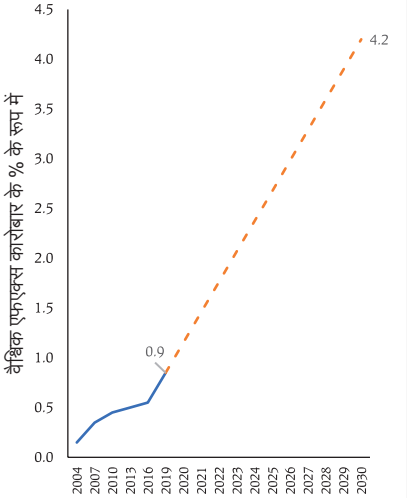

चार्ट 13: कोविड के आघात

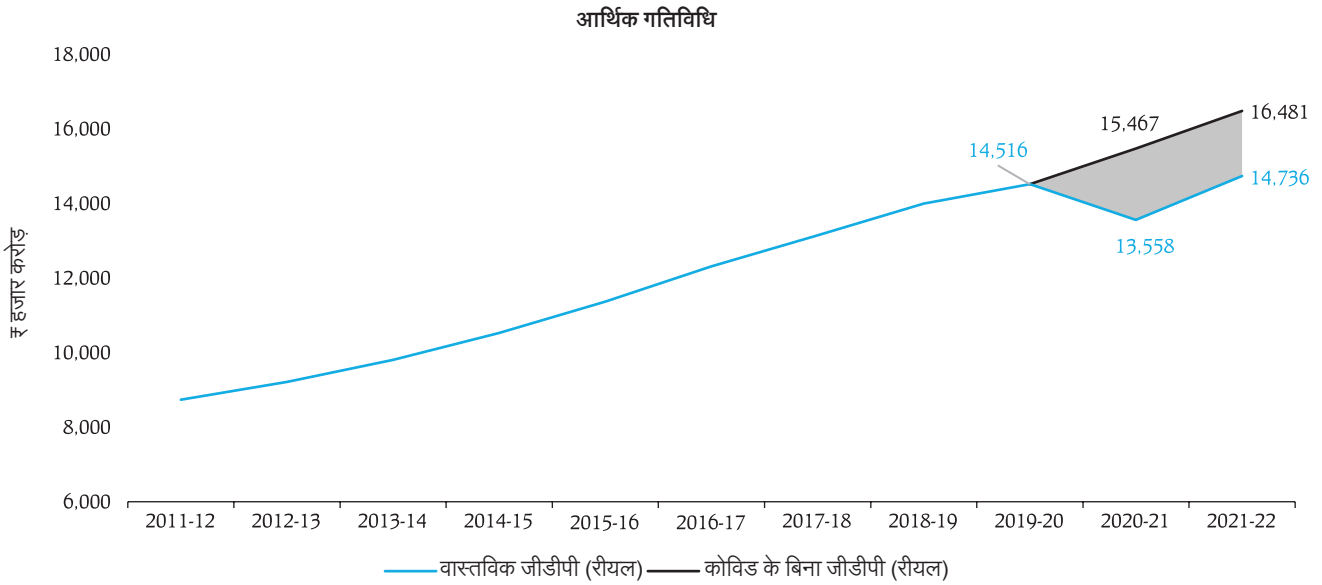

चार्ट 14: विश्व-स्तरीय अवसंरचना

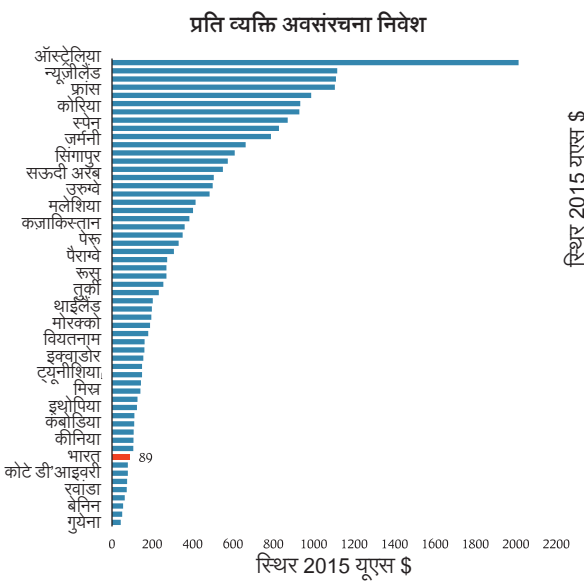

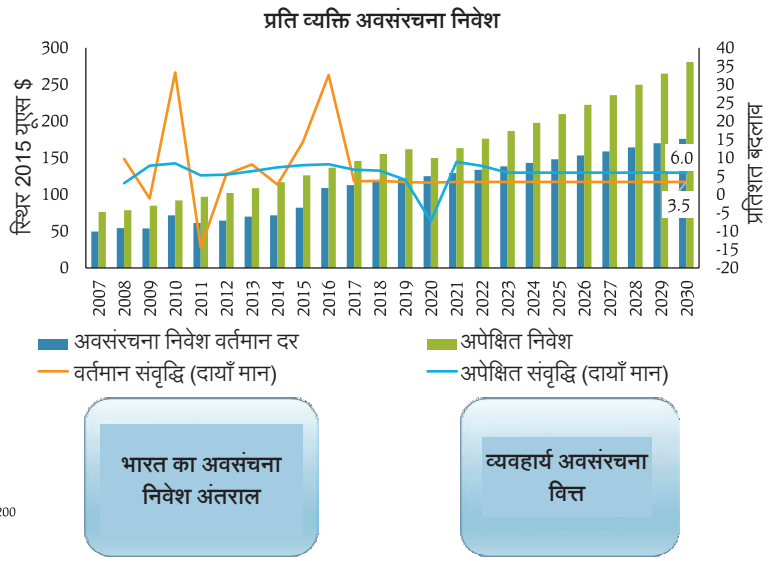

चार्ट 15: उच्च गुणवत्ता श्रम बल

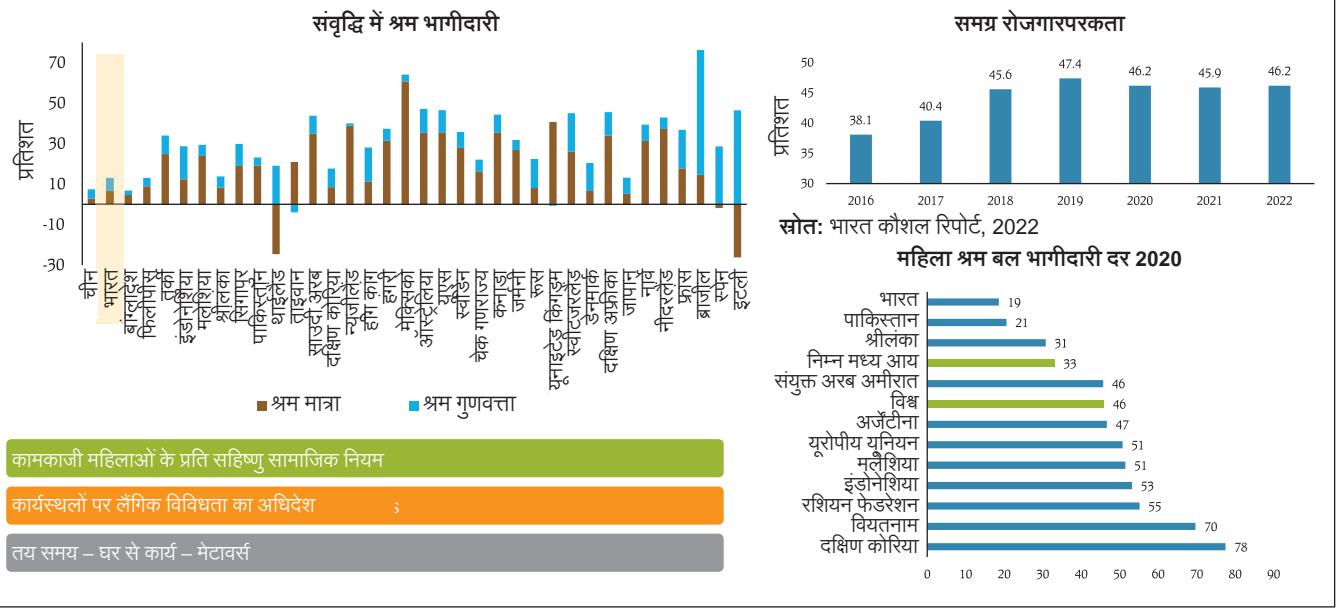

चार्ट 16: हरित भारत

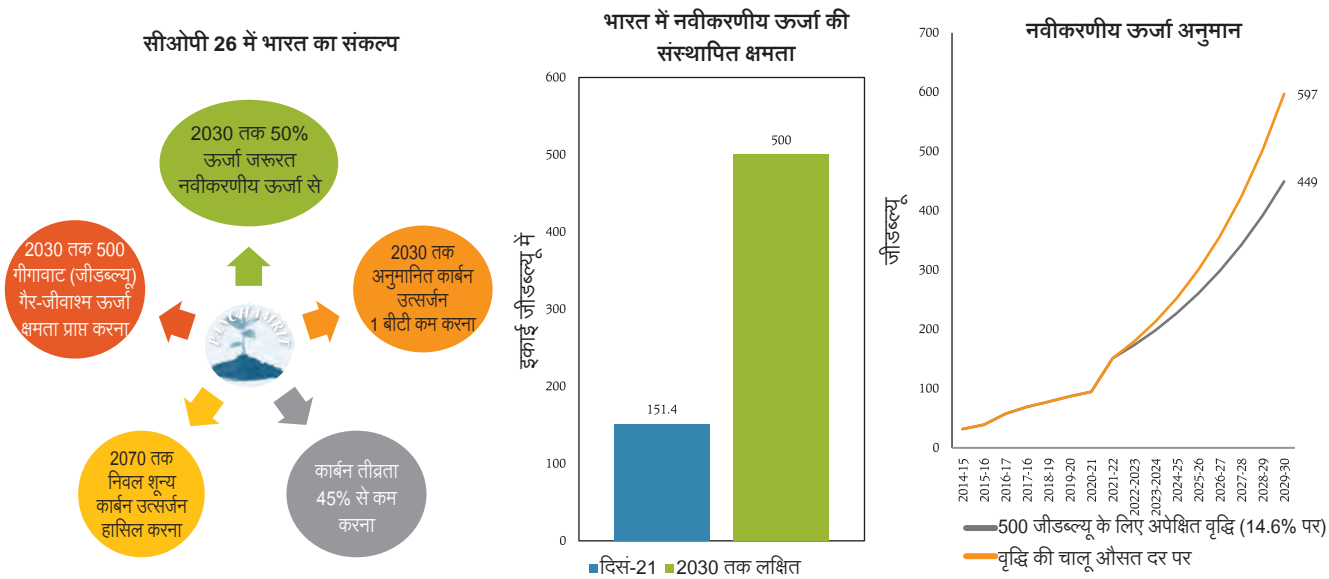

चार्ट 17: परस्पर तुलना

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक जीडीपी

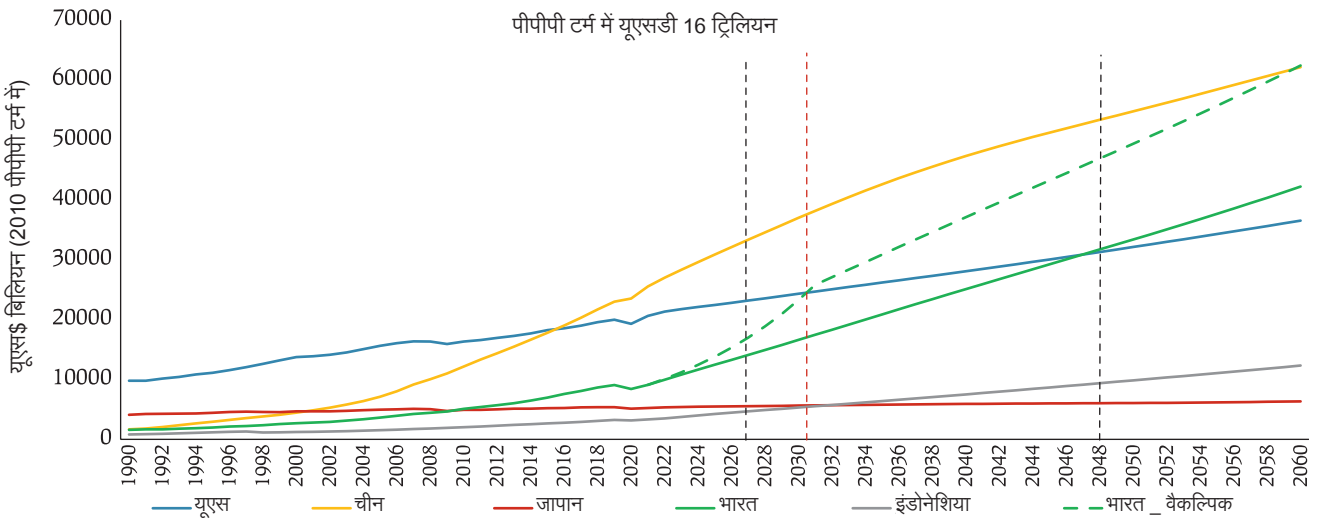

स्रोत: ओईसीडी (2021)